

# ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुसार, प्रत्येक राष्ट्र को सशस्त्र हमले का सामना करने पर “व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा का अंतर्निहित अधिकार” प्राप्त है। यह मूलभूत कानूनी सिद्धांत ईरान के उस अधिकार की पुष्टि करता है कि वह हाल ही में इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए आक्रामक कृत्यों के जवाब में अपनी संप्रभुता और अपने लोगों की रक्षा करे। 13 जून 2025 को इज़राइल द्वारा ईरान पर बिना उकसावे के किया गया हमला और इसके बाद 21 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया हमला, दोनों ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना किए गए थे। इस प्रकार, ये कृत्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) का स्पष्ट उल्लंघन हैं, जो किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के उपयोग या धमकी को सख्ती से प्रतिबंधित करता है, जब तक कि इसे सुरक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत न किया गया हो या यह आत्मरक्षा में न हो।

इज़राइल द्वारा प्रदर्शित आक्रामकता के विपरीत, ईरान ने शांति और स्थिरता के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता दिखाई है। सहस्राब्दियों पुरानी सभ्यता वाला राष्ट्र होने के नाते, ईरान ने दो शताब्दियों से अधिक समय तक किसी अन्य देश के खिलाफ युद्ध शुरू नहीं किया है। यह परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) का हस्ताक्षरकर्ता बना हुआ है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ सक्रिय सहयोग बनाए रखता है, और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करता है। फिर भी, ईरान एक दुष्ट राज्य से निरंतर सैन्य और आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा पैदा करता है: इज़राइल।

## अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति इज़राइल की अवज्ञा

मध्य पूर्व में इज़राइल की आक्रामकता का रिकॉर्ड व्यापक और अच्छी तरह से प्रलेखित है। इसने लेबनान, सीरिया और यमन में संप्रभु क्षेत्रों पर बमबारी की है, बिना कानूनी औचित्य या संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के। इन कार्यों ने पूरे क्षेत्रों को अस्थिर किया, मानवीय संकटों को जन्म दिया, और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के क्षरण में सीधे योगदान दिया। इसके अलावा, इज़राइल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर लंबे समय से कब्जा, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का व्यवस्थित उल्लंघन, और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का पालन करने से इनकार, स्पष्ट रूप से इसे मध्य पूर्व में आक्रामक, न कि पीड़ित, के रूप में चिह्नित करता है।

बार-बार अंतरराष्ट्रीय निंदा के बावजूद, इज़राइल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा के बाध्यकारी प्रस्तावों को नजरअंदाज करता रहा है। इसने जनवरी 2024 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के आदेशों की अवहेलना की, जिसमें अवैध बस्ती विस्तार को रोकने, गाजा में मानवीय सहायता की अनुमति देने, और वेस्ट बैंक में बस्तियों को खत्म करने का निर्देश दिया गया था। अनुपालन के बजाय, इज़राइल ने अपनी क्रूरता की मुहिम को तेज किया, 2023 और 2025 में गाजा पर पूर्ण घेराबंदी लागू की। इन घेराबंदियों के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर भुखमरी हुई – जो अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत युद्ध अपराध है – और पत्रकारों, अस्पतालों, और आवासीय इमारतों सहित नागरिकों पर जानबूझकर निशाना साधा गया।

हाल के सबसे निंदनीय खुलासों में से एक मानवीय सहायता का हथियारीकरण है। इज़राइल द्वारा बनाई गई तथाकथित “गाजा मानवीय फाउंडेशन” को एक जाल के रूप में उजागर किया गया है, जो बेताब नागरिकों को वितरण बिंदुओं पर लुभाने के लिए बनाया गया था, केवल उन्हें गोली मारने के लिए – यह एक ऐसी रणनीति है जो जिनेवा सम्मेलनों का उल्लंघन करती है और मानवता के खिलाफ अपराधों के बराबर है। हार्वर्ड के एक हालिया अध्ययन का अनुमान है कि गाजा के 2.2 मिलियन निवासियों में से 377,000 लोग अब लापता हैं और उन्हें मृत मान लिया जाना चाहिए। ये आकस्मिक हताहत नहीं हैं – ये एक निरंतर और जानबूझकर किए गए नरसंहार अभियान के परिणाम हैं।

परमाणु क्षेत्र में इज़राइल का व्यवहार भी गंभीर चिंताएं पैदा करता है। यह दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जो एनपीटी पर हस्ताक्षर करने और उसकी पुष्टि करने से इनकार करते हैं, जिससे यह आईएईए के निरीक्षणों से बचता है। इसने कुख्यात NUMEC मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका से उच्च संवर्धित यूरेनियम चुराकर एक गुप्त परमाणु शस्त्रागार बनाया है। इसके अलावा, अपनी परमाणु क्षमताओं को घोषित करने से इनकार करके, इज़राइल अमेरिकी कानून के तहत जवाबदेही से बचता

है, विशेष रूप से सिमिंगटन संशोधन, जो एनपीटी ढांचे के बाहर परमाणु हथियार विकसित करने वाले देशों को सैन्य सहायता पर रोक लगाता है। अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और घरेलू कानूनों के इन जानबूझकर किए गए उल्लंघनों को लगातार अमेरिकी प्रशासनों द्वारा सहन किया गया – वास्तव में, सक्षम किया गया।

ईरान की शांतिपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को दबाने की अपनी उत्सुकता में, संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल दोनों ने ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमले किए हैं, जो पूरी तरह से आईएईए की निगरानी में हैं। ये लापरवाह कृत्य रेडियोधर्मी सामग्रियों के रिसाव का जोखिम उठाते हैं, नागरिकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, और क्षेत्र की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाते हैं – फिर भी इन्हें झूठे तौर पर “रक्षात्मक” या “निवारक” उपायों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

## **निष्कर्ष: शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा इज़राइल**

यह तेजी से स्पष्ट हो रहा है कि इज़राइल एक दुष्ट राज्य के रूप में कार्य करता है – कानून से परे, अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही से ऊपर, और मानवीय पीड़ा के प्रति उदासीन। यह न केवल मध्य पूर्व में, बल्कि विश्व स्तर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। यह व्यवस्थित रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करता है, मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करता है, और बिना सजा के एक सैन्यवादी और विस्तारवादी एजेंडे को आगे बढ़ाता रहता है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अब और निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। नरसंहार निवारण संधि और “रक्षा की जिम्मेदारी” (R2P) ढांचे के तहत, फिलिस्तीनी लोगों की रक्षा के लिए नैतिक और कानूनी दायित्व है। विश्व को तत्काल इज़राइल पर व्यापक आर्थिक और राजनयिक प्रतिबंध लगाने, सख्त हथियार प्रतिबंध लागू करने, और **संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 377 (“शांति के लिए एकजुट”)** के तहत सैन्य हस्तक्षेप पर विचार करने की आवश्यकता है, जो सुरक्षा परिषद के कार्य करने में विफल रहने पर सामूहिक कार्रवाई की अनुमति देता है।

द्विविधा का समय समाप्त हो चुका है। विश्व को इज़राइल को जवाबदेह ठहराना होगा। ईरान का आत्मरक्षा का अधिकार न केवल कानूनी है – यह निरंतर आक्रामकता के सामने अनिवार्य है। वैश्विक शांति और न्याय की मांग है कि इज़राइल के दुष्ट व्यवहार का सामना किया जाए और इसे निर्णायक अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई के माध्यम से नियंत्रित किया जाए।